भाजपा सरकार के तुगलकी फ़रमान ने ली मासूम बच्ची की जान

फ़रीदाबाद (म.मो.) सरकार के तुगलकी फरमान की कीमत डबुआ कालोनी निवासी 11 महीने की मासूम बच्ची को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बीमार बच्ची के परिजनों के पास आधार कार्ड न होने के कारण उसका इलाज के लिए बीके अस्पताल में कार्ड नहीं बनाया गया था। यह तो सिर्फ उदाहरण मात्र हर रोज बीके अस्पताल में आने वाले दर्जनों गरीब तबके के मरीजों को सिर्फ आधार कार्ड न होने के कारण बिना इलाज किए लौटा दिया जाता है।

खुद को गरीबों की हितैषी बताने वाली केंद्र और प्रदेश की जुमला सरकार गरीब तबके के लोगों को कभी नोटबंदी तो कभी जीएसटी और कभी आधार कार्ड की अनिवार्यता के नाम पर परेशान करने पर तुली हुई है। अप्रैल 2016 में सरकार ने बीके अस्पताल को ऑनलाइन कर दिया। जिसके बाद इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए आधार कार्ड लाना अनिवार्य कर दिया है। मरीजों के लिए बनाए जाने वाले ओपीडी कार्ड में आधार कार्ड नंबर दर्ज करने का सरकार ने जबरन नियम बना लिया। जो मरीज आधार कार्ड नहीं लाते उन्हें इलाज के बिना ही लौटा दिया जाता है।

इसी जबदस्ती के नियम के कारण बच्ची अन्नू को अपनी जान गंवानी पड़ी। अन्नू करीब एक सप्ताह से उल्टी दस्त की बीमारी से पीड़ित थी। 6 दिसंबर को एक निजी क्लीनिक के डॉक्टर ने उसे बीके अस्पताल ले जाने की सलाह दी थी। जिसके बाद कोमल अपनी बेटी को बीके अस्पताल लेकर आई थी। आधार कार्ड न होने पर जब ओपीडी कार्ड नहीं बना तो वह बच्ची को आपातकालीन कक्ष में ले गई।

वहां मौजूद ड्यूटी डाक्टर ने बाहर की दवा लिख कर अपना पल्ला झाड़ लिया। बाहर से इंजेक्शन लाने पर उसे डाक्टर अथवा स्टाफ नर्स न लगाने की जहमत नहीं उठाई। नर्सिंग छात्रा द्वारा इंजेक्शन लगाते ही अन्नू ने वहीं पर दम तोड़ दिया।

मामले में परिजनों द्वारा हंगाम किए जाने के बावजूद सीएमओ डॉ. गुलशन अरोड़ा और अस्थाई पीएमओ डॉ. राजीव बातीश ने लापरवाही बरतने वाले ड्यूटी डाक्टर और स्टॉफ नर्स के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर जांच तक करवाने की जरूरत महसूस नहीं की।

इस तरह की घटना बीके अस्पताल में कोई पहली बार नहीं हुई है। सरकार के तुगलकी फरमान के कारण आधार कार्ड न होने की वजह से आए दिन गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को लौटा दिया जाता है। सरकारी रिकॉर्ड में जिले की आबादी भले ही 17-18 लाख हो।

लेकिन वास्तव में फ़रीदाबाद की आबादी 25 लाख से ज्यादा है। सरकार करीब 17 लाख से ज्यादा लोगों के आधार कार्ड बनाने के दावे कर रही है। लेकिन इनमें से अभी भारी संख्या में लोगों के पास आधार कार्ड पहुंचे ही नहीं है। जिले में अभी भी करीब 8 से 10 लाख लोग है, जिन्होंने आधार कार्ड बनाने के लिए आवेदन ही नहीं किया। इनमें ज्यादा गरीब और मज़दूर तबके के लोग शामिल है। ऐसे में सरकार के इस तुगलकी फ़रमान के कारण इन लोगों को सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा है। मजबूरी में इन लोगों को निजी डॉक्टरों के हाथों लुटना पड़ रहा है।

नीमका जेल में तलाशी अभियान या विभागीय नाटक

फ़रीदाबाद (म.मो.) अपनी पीठ स्वयं थपथपाते हुये जेल प्रशासन द्वारा फ़ैलाई गयी खबरों में कहा गया है कि दिनांक 11 दिसम्बर को नीमका जेल में अचानक छापा मारकर भारी तलाशी अभियान चलाया गया। मिली जानकारी के अनुसार विभाग के अतिरिक्त आईजी हरीश कुमार रंगा ने अपने साथ लाये 12 जेल-कर्मियों की मदद से प्रात: 6 बजे तलाशी अभियान चलाया जो सायं 6 बजे तक चला। मगर इसमें मिला कुछ नहीं।

विदित है कि जेल की व्यवस्था कुछ ऐसी होती है कि इसमें अचानक छापामारी जैसी कोई कार्यवाही लगभग असंभव होती है। जेल के मुख्य द्वार पर भीतर की ओर ताला लगा होता है। जिसे बाहर खड़े संतरी द्वारा भीतर सूचना देने पर ही खोला जाता है। भीतर सुचना देते ही अचानक वाली बात तो खत्म हो जाती है। बाहरी मुख्य द्वार के बाद जेल के भीतर खुलने वाले बड़े द्वार पर भी ताला लगा होता है, फ़िर उसे खोला जाता है। इन द्वारों से करीब आधा पौना किलोमीटर चल कर जेल की बैरकें बनी हैं जिनमें तमाम कैदी रहते हैं। जाहिर है, ऐसे में अचानक छापे वाली कोई बात रह नहीं जाती।

उक्त बाहरी व भीतरी द्वारों के मध्य भाग को ड्योढी कहा जाता है, जहां जेल अधीक्षक व अन्य अधिकारी तथा स्टाफ़ बैठता है। ऐसे में जब भी कोई मुख्य द्वार में प्रवेश करेगा तो उसकी पूर्व सूचना सभी अधिकारियों व स्टाफ़ को हो जायेगी और वो सचेत हो जायेंगे। इसी व्यवस्थागत कवच के संरक्षण में जेल अधीक्षक बेखौफ़ होकर अपने मनचाहे काले धंधे चलाता है।

'मज़दूर मोर्चा' के विगत अंकों में विस्तृत विवरण दिया गया है कि किस प्रकार नीमका जेल अधीक्षक अनिल कुमार अपने काले धंधों को अंजाम देता है। उसकी मर्जी के बगैर जेल में मोबाइल व सुल्फ़ा तो क्या एक सूई तक भी प्रवेश नहीं पा सकती। जहां जेल अधीक्षक की मोटी लूट-कमाई का बड़ा साधन कैदियों का राशन डकारना व कैंटीन के माध्यम से जरूरत की हर चीज़ ब्लैक के भाव बेचना है; वहीं अन्य छोटे-बड़े कर्मचारी मोबाइल व सुल्फ़े के अलावा कैदियों को छोटी-मोटी रियायतें देकर अपनी जेबें गर्म करते हैं।

यदि जेल अधीक्षक अनिल खुद बड़ी डकैतियां न मार कर ईमानदारी से काम करे तो उसके आधीन काम करने वाले अन्य कर्मचारी भी किसी अवैध धंधे को संरक्षण देने के बजाय उसकी रोक-थाम करेंगे। गतांक में, सुधी पाठकों ने पढा होगा कि किस प्रकार छोटे कर्मचारी ने एक मोबाइल पकड़ा था, जिसे जेल अधीक्षक ने 83 हजार लेकर केस रफ़ा-दफ़ा कर दिया था। रफ़ा-दफ़ा करने का यही काम बहुत सस्ते में वे छोटे मुलाजिम भी तो कर सकते थे। जेल अधीक्षक की कार्यप्रणाली एवं घूसखोरी से प्रेरित होकर ही छोटे मुलाजिम अवैध धंधों को पकड़ने की बजाय छोड़ कर अपनी कमाई करते हैं।

इस तरह के औचक तलाशी के नाटक पहले भी बहुत होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे और मोबाइल सहित सभी अवैध धंधे भी यूं ही चलते रहेंगे।

निजी प्रयोगशालाओं के हाथों लुट रहे हैं मरीज

फ़रीदाबाद (म.मो.) खुद को गरीब जनता की हितैषी होने का दावा करने वाली भाजपा सरकार की लापरवाही के कारण बादशाह खान अस्पताल में आने वाले मरीजों को निजी प्रयोगशालाओं के हाथों लुटने को मजबूर होना पड़ रहा है। कहने के लिए अस्पताल में प्रयोगशाला मौजूद है। लेकिन कर्मचारियों की भारी कमी के कारण प्रयोगशाला में जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही होती है।

कर्मचारियों की भारी कमी होने के बावजूद सीएमओ डॉ. गुलशन अरोड़ा ने इस अस्पताल की प्रयोगशाला को 24 घंटे खोलने के आदेश दिए हुए हैं। लेकिन 24 घंटे काम करने के लिए प्रयोगशाला के पास जरूरत के मुताबिक कर्मचारी मौजूद नहीं है। प्रयोगशाला में जरूरत तो करीब 30 लैब तकनीशियन की है लेकिन यहां पद 14 लैब तकनीशियन के ही हैं। इसमें से भी सिर्फ नौ लैब तकनीशियन मौजूद हैं। इनमें पांच स्थाई और चार अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हैं। यानी 24 घंटे की तीन शिफ्टों में तीन तीन ही लैब तकनीशियन तैनात रहते है। इनमें से एक एक लैब तकनीशियन की ड्यूटी बच्चों की नर्सरी और ओपीडी में होती है। सात लैब तकनीशियन के भरोसे हर रोज हजारों लोगों की बीमारियों की जांच करने की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा प्रयोगशाला में सिर्फ एक पैथोलॉजिस्ट डॉ. एसएस दहिया तैनात हैं। जबकि 24 घंटे चलने वाली प्रयोगशाला में एक पैथोलॉजिस्ट के अलावा एक बॉयो कैमिस्ट और एक माइक्रो बॉयोलॉजिस्ट डाक्टर की भी आवश्यकता है।

जानकार सूत्रों के मुताबिक ओपीडी, आपातकालीन कक्ष और विभिन्न वार्डो से हर रोज करीब ढाई से तीन हजार मरीजों के सैम्पल जांच के लिए प्रयोगशाला में जाते हैं। लैब तकनीशियन की भारी कमी के कारण इन सैम्पलों की रिपोर्ट किस तरह की आती होगी, इसका अंदाजा कोई भी आसानी से लगा सकता है। अव्वल तो मरीजों को अपनी जांच रिपोर्ट सही समय पर मिलती ही नहीं है और यदि जांच रिपोर्ट मिल भी जाए तो अस्पताल के डाक्टर रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर देते हैं। डाक्टरों को इस प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट पर भरोसा नहीं होता। क्योंकि इसकी रिपोर्ट भरोसे लायक है ही नहीं। और भरोसा हो भी जाए तो कमीशन के कारण डाक्टर मरीजों को निजी प्रयोगशाला में भेजते हैं।

अस्पताल की ओपीडी, आपातकालीन कक्ष और वार्डो में मरीजों की जांच के सैम्पल नर्सिंग छात्राओं द्वारा लिए जाते है। ऐसे में यह छात्राएं कई बार सैम्पल सही तरीके से नहीं ले पातीं। और सैम्पल सहीं तरीके से ले भी लें तो अक्सर सैम्पल बदल जाते है। जिसके कारण मरीजों को अपनी जांच रिपोर्ट हासिल करने के लिए कई कई बार रक्त के सैम्पल देने पड़ते हैं।

प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट लेना भी कोई आसान काम नहीं हैं। जांच रिपोर्ट वितरण करने के लिए प्रयोगशाला के पास कोई उचित व्यवस्था नहीं है। जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद उनकी गड्डी बना कर प्रयोगशाला के दरवाजे के पास एक टेबल पर रख दिया जाता है। जहां से मरीजों के परिजनों को खुद रिपोर्ट छांट कर ले जानी होती है। ऐसे में मरीजों की जांच रिपोर्ट अक्सर गुम हो जाती है।

सरकारी प्रयोगशाला से निराश होने के बाद मरीजों को आसपास स्थित प्रयोगशाला में महंगी कीमत पर अपनी जांच करवाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अस्पताल के ज्यादातर डाक्टरों को बीके चौक पर स्थित शांति लैब की रिपोर्ट पर ज्यादा भरोसा होता है। शांति लैब में हर समय बीके अस्पताल के मरीजों की जांच करवाने के लिए भीड़ लगी रहती हैं। ऐसा नहीं कि शहर की अन्य निजी प्रयोगशालाओं की जांच रिपोर्ट अच्छी नहीं होती। लेकिन शांति लैब से हर महीने डॉक्टरों मिलने वाले भारी भरकम कमीशन के कारण बीके के मरीजों को वहां जांच के लिए भेजा जाता है। क्योंकि कमीशन का एक हिस्सा सीएमओ डॉ. गुलशन अरोड़ा के पास भी पहुंचता है जिसके कारण सबकुछ जानकर भी वे अंजान बने रहते हैं?

डिस्पेंसरियों में इलाज के नाम पर किया जा रहा है मजाक

फ़रीदाबाद। (म.मो.) हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के दावे करने वाली मनोहर लाल खट्टर सरकार गरीबों तबके के मरीजों के साथ इलाज के नाम पर भद्दा मजाक कर रही है। सरकार ने कहने को गरीब तबके के लोगों को उनके घरों के नजदीक इलाज की सुविधा देने के लिए जगह जगह डिस्पेंसरियां खोली हुई हैं। लेकिन इन डिस्पेंसरियों में इलाज के नाम पर मरीजों को बहकाने के लिए चंद रंग बिरंगी गोलियां थमा दी जाती हैं और उन्हें बीके अस्पताल जाने का रास्ता दिखा दिया जाता है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही इसी तरह की डिस्पेंसरियों में शामिल है संजय कॉलोनी, सैक्टर 23 स्थित डिस्पेंसरी। यह डिस्पेंसरी नगर निगम के जर्जर हालत कम्युनिटी सेन्टर में चल रही है। डिस्पेंसरी में स्थाई कर्मचारियों में एसएमओ (प्रभारी) डॉ. संजीव भगत, दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. परविंद्र कौर और सहायक (क्लर्क) राजेश वत्स तैनात हैं। जबकि एनएचएम के नाम पर ठेकेदारी में डॉ. अर्चना, आर्युवैदिक डॉ. रितु, दो फार्मासिस्ट और एक एएनएम तैनात है।

गत पांच दिसम्बर से चल रही एनएचएम के डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों की हड़ताल के कारण डिस्पेंसरी का काम लगातार ठप्प है। हड़ताल के पहले दिन मजदूर मोर्चा ने डिस्पेंसरी का दौरा किया तो वहां क्लर्क राजेश वत्स के अलावा अन्य कोई डाक्टर और कर्मचारी मौजूद नहीं था। जिसके बाद मजदूर मोर्चा द्वारा लगातार डिस्पेंसरी पर नजर रखी जाने लगी। लेकिन इस क्लर्क के अलाव अन्य कोई डाक्टर और कर्मचारी काम पर नहीं आया। जबकि हड़ताल तो एनएचएम कर्मचारियों और डाक्टरों की है। लेकिन हड़ताल की आड़ में यहां तैनात स्थाई डॉ. संजीव भगत और डॉ. परविंद्र कौर भी छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं।

जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. परविंद्र कौर (अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की धर्मपत्नी) की तैनाती पूरी तरह संदेह के घेरे में है। डिस्पेंसरी में आने वाले दंत चिकित्सक के लिए काम करने लायक न तो कोई विशेष कुर्सी है और व अन्य उपकरण। इसके बावजूद यहां दंत चिकित्सक की नियुक्ति का मकसद खानापूर्ति से अधिक कुछ नहीं हैं। मौजूदा हालात में कोई भी दंत चिकित्सक दांतों का इलाज कर ही नहीं सकता। यहां दंत चिकित्सक की नियुक्ति का अर्थ केवल उसे बैठा कर वेतन देने के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। डिस्पेंसरी में आए या न आए काम तो कुछ करना नहीं है।

लोगों के स्वास्थ्य पर करोड़ों रुपये सालाना खर्च करने के दावे करने वाली भाजपा सरकार के दावे डिस्पेंसरी की हालत को देख कर पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं। डिस्पेंसरी में हर रोज करीब 100 से डेढ़ सौ मरीज अपनी जांच और इलाज के लिए आते हैं लेकिन इसके बावजूद पीने के पानी और शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। डाक्टर और कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए एक शौचालय मौजूद है लेकिन मरीजों को इसमें जाने की इजाजत नहीं दी जाती। अपनी बारी के इंतजार में मरीजों को खड़े रहना पड़ता हैं क्योंकि उनके बैठने तक का इंतजाम नहीं है।

सरकार जिले में डिलवरी हटों को 24 घंटे खुला रखने का दावा करती है। इस डिस्पेंसरी में भी नाम के लिए एक डिलीवरी हट है। लेकिन शाम ढलते ही डिस्पेंसरी के साथ साथ डिलीवरी हट में भी ताला लग जाता है। प्रसूति कक्ष के नाम पर डिस्पेंसरी में सिर्फ दो बिस्तर और इन्हें ढकने के लिए हरी चादरों की दो दीवार ही मौजूद हैं। इसके अलावा प्रसूति के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष बैड और अन्य उपकरण मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं है कि सीएमओ डॉ. गुलशन अरोड़ और इलाके के भाजपा विधायक मूलचंद शर्मा को डिस्पेंसरी की हालत के बारे में पता नहीं है। सबकुछ जानने के बावजूद ये लोग अपनी आंखे मूंद बैठे हुए हैं।

राजनीतिक संरक्षण में कर्ण पार्क में बढ़ते अवैध कब्जे

करनाल (जे के पी के) करनाल शहर के बीचों-बीच जनता के लिये बना कर्ण पार्क बस स्टैण्ट के साथ लगता वह क्षेत्र है जहां ज़िला के लोग़ों का आना-जाना लगा रहता है। कर्ण पार्क एक सुन्दर जगह रही है जो लोगों को सुबह शाम की सैर से लेकर दोपहर विश्राम के लिये एक वरदान साबित हुयी है। वह पार्क आज सरकारी उपेक्षा व राजनीति का शिकार होने से नहीं बच पाया जबकि कुछ लोगों की नज़र इस पार्क के हर कोने को घेरने पर लगी है।

स्थानीय नगर निगम भी इस पार्क की खूबसूरती को मिटाने में अब अतिक्रमणकारियों के साथ आ खड़ी हुई है। समाज सेवा, जन सेवा व राजनीतिक लोगों ने संस्था के नाम पर प्रस्ताव पार्षदों व विधायकों के माध्यम से लाने शुरू कर दिये हैं। लगता है भाजपा सरकार के 5 साल पूरे होने से पहले कई संस्थायें अलग-अलग कोने पर काबिज हो जायेगी और पार्क को दीन दयाल उपाध्याय कॉलोनी का नाम दे दिया जायेगा।

करनाल के इस भव्य पार्क पर यूं तो तमाम कई सामाजिक संस्थाओं की नज़र है लेकिन करनाल मानव सेवा संघ के नाम से चर्चित संस्था जिसका सर्वेसर्वा मास्टर हरिराम उर्फ प्रेम मूर्ति पुत्र स्वर्गीय चिरन्जी लाल है, ने पक्के तौर पर अपना ठिकाना कर्ण पार्क में जमा लिया है।

भू-माफिया राजनीतिज्ञ, धर्मान्ध राजनीतिज्ञों व कुछ पार्षदों को अपने पक्ष में करते हुये पार्क में कब्जा करने में लागा हुआ है। पाखंड के नाम पर कुछ पानी की टंकियां जिनमें पानी हो-न-हो लेकिन बीच चौराहों पर मानव सेवा संघ का विज्ञापन दिखाते मिलेगा।

दोपहर दाल-चावल बना कर संस्था द्वारा भोजन का नाम दिया जाता है। जिसके लिये शहर भर से पैसा इकट्ठा किया जाता है। मानव सेवा संघ ने अब पार्षदों से मिली भगत कर कर्ण पार्क के बीचों-बीच भोजनालय बनाना तय कर लिया।

करनाल में जब किसी को अपने परिवार के लिये कभी कोई बरसी, जन्म दिन मनाना या कोई मिटिंग करनी हो तो वह पार्क में उत्सव के लिये मास्टर हरिराम के पास जा पार्क की बुकिंग कर लेता है। प्रोग्राम के लिये मानव सेवा संघ अपनी सेवायें पेश करता है। जिसमें भण्डारा के लिये भोजन, हलवा, चाय पकोड़े, प्रसाद आदि मानव सेवा संघ द्वारा दी जाती है और उसके एवज में कम्यूनिटी हाल का किराये का मौखिक अनुमान लगा कर दान के रूप में वसूला जाता है।

सूत्रों से पता चला है कि शहर के कुछ आढ़तियों द्वारा मानव सेवा संघ को प्रत्येक वर्ष जो अनाज दान दिया जाता है उसी को बेचकर मानव सेवा संघ द्वारा भण्डारा करने वालों से पैसे वसूल किये जाते हैं।

उल्लेखनीय है कि मास्टर हरिराम ने कुछ पार्षदों के हस्ताक्षर करवा कर 4100 वर्ग गज पार्क का हिस्सा न्यूनतम दर पर खरीदने की मांग कर दी। जिस पर एक स्थानीय पत्रकार आनन्द शर्मा ने तत्कालीन उपायुक्त बलबीर मलिक को शिकायत करके रोक लगवा दी थी।

उल्लेखनीय है कि हरिराम मानव सेवा संघ के संचालक इस योजना में सफल न हुआ तो भू-माफ़िया पार्षदों से मिलकर जगह हथियाने में कामयाब हो गया जिसे नगर निगम के हाउस ने भी पास कर दिया। यानी कि मानव सेवा संघ को कीमत भी न देनी पड़ी और जो कीमत नगर निगम को पार्क का कुछ हिस्सा बेचने पर मिलनी थी वह भी गई, और बिना कीमत के जगह मानव सेवा संघ को अलाट कर दी।

हैरानी की बात तो ये है कि पार्क के कुछ हिस्से की भूमि पर पुरूषोतम चेरीटेबल ने भी अपना कब्ज़ा जमा रखा है जिसके बारे में शहर में चार्चा है कि मानव सेवा संघ ने पुरूषोतम चेरीटेबल को बेच दी है। परन्तु नगर निगम के अधिकारियों पर जूं भी नहीं रेंगती। अब पार्क जूआ, सट्टा व शराबियों का घर बन चुका है।